I मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 2025 में, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उच्च टैरिफ, वर्धित नीतिगत अनिश्चितता, बढ़ते सार्वजनिक ऋण और भू-राजनैतिक तनाव के बीच 3.4 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 3.3 प्रतिशत) के साथ सुदृढ़ता प्रदर्शित की। इन विपरीत परिस्थितियों को आयात की फ्रंटलोडिंग, आपूर्ति-श्रृंखला पुनर्संरेखण, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संबंधित निवेश में वृद्धि से काफी हद तक संतुलित किया गया। अप्रैल और मई 2025 की अवधि में टैरिफ तनाव रहा, इसके अलावा वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ व्यापक रूप से अनुकूल रहीं। 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए परिदृश्य[1] 3.1 प्रतिशत के मध्यम विस्तार की ओर इशारा करता है, जो इसके दीर्घकालिक औसत (2000-19) 3.7 प्रतिशत से कम है। 2026 में 2.8 प्रतिशत[2] की अनुमानित विश्व व्यापार (संयुक्त रूप से वस्तु और सेवाएं) मात्रा वृद्धि, भू-राजनैतिक परिदृश्य में बदलाव और ऊर्जा की कीमतों से प्रेरित मुद्रास्फीति जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है। विकास-मुद्रास्फीति की उभरती गतिशीलता, विशेष रूप से पश्चिम एशिया संघर्ष के परिणामस्वरूप आपूर्ति के आघातों से उत्पन्न मुद्रास्फीति जोखिमों की वृद्धि के चलते केंद्रीय बैंकों के लिए विकास पर प्रतिकूल प्रभाव-विस्तार को कम करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है, जो मौद्रिक नीति पथों के सतर्क समायोजन की जरूरत को बताता है।

I.2 2025-26 के दौरान भारत 7.6 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 7.1 प्रतिशत)[3] की दर से विस्तार करते हुए सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा, जो मजबूत घरेलू खपत, निरंतर निवेश, सक्रिय नीतिगत पहल और मजबूत समष्टि आर्थिक आधार से समर्थित है। वर्ष के प्रमुख भाग के दौरान मुद्रास्फीति स्पष्ट रूप से कम रही। वित्तीय क्षेत्र बैंकों और गैर-बैंकों के अच्छे तुलन-पत्रों, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और पूंजी बफर के बल पर सुदृढ़ बना रहा, जिससे दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि संभव हुई। राजकोषीय मोर्चे पर, व्यय गुणवत्ता में सुधार और राजस्व व्यय में नियंत्रण करने के साथ-साथ समेकन के प्रयास जारी रहे। पोर्टफोलियो निवेश में निवल बहिर्वाह देखने को मिला, इसके बावजूद भी मामूली चालू खाते घाटे (सीएडी) और पर्याप्त विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों ने बाह्य क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान की।

I.3 ऊर्जा और कमोडिटी की ऊंची कीमतों, बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और वैश्विक व्यापार नीतियों में अनिश्चितताओं के चलते चुनौतीपूर्ण बाह्य वातावरण के बावजूद 2026-27 में घरेलू अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बने रहने की उम्मीद है। विकास की संभावनाएं मजबूत घरेलू मांग, विकास-चालक के रूप में निर्यात पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता और स्थिर नीतिगत वातावरण के साथ भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक आधार से समर्थित हैं।

[1,2] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डबल्यूईओ), अप्रैल 2026, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़)।

[3] इस रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) डेटा के सभी संदर्भ 27 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ) द्वारा जारी, नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ, दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) पर आधारित हैं, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

2. 2025-26 का मूल्यांकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

I.4 2025 में, लंबे समय तक भू-राजनैतिक तनाव, व्यापार संबंधी अनिश्चितता और उच्च ऋण स्तर जैसी कई विपरीत परिस्थितियों के मध्य वैश्विक विकास 3.4 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 3.3 प्रतिशत)[4] के साथ सुदृढ़ बना रहा। ये विपरीत परिस्थितियाँ राजकोषीय और मौद्रिक सहायता, उदार वित्तीय स्थितियों और प्रौद्योगिकी में बढ़ते निवेश जैसी अनुकूल परिस्थितियों से संतुलित थीं। वैश्विक मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 5.8 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.1 प्रतिशत हो गई, जो ऊर्जा की कीमतों में नरमी, आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के सामान्यीकरण के प्रभाव को दर्शाता है, जबकि कोर और सेवाओं की मुद्रास्फीति स्थिर बनी रही। हालांकि, अवस्फीतिकारी प्रक्रिया विभिन्न देशों में असमान रही जबकि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सेवा मुद्रास्फीति में सापेक्ष स्थिरता रही।

I.5 2025 में विश्व वस्तु और सेवाओं के व्यापार की मात्रा में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो विश्व जीडीपी की वृद्धि से अधिक है। पण्य व्यापार की मात्रा में 4.6 प्रतिशत (2024 में 2.7 प्रतिशत)[5] की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से उच्च टैरिफ की प्रत्याशा में आयात की फ्रंटलोडिंग और टैरिफ उपायों से छूट प्राप्त प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में वृद्धि से प्रेरित है। दूसरी ओर, वैश्विक सेवा व्यापार की मात्रा 5.3 प्रतिशत (2024 में 7.8 प्रतिशत) की मध्यम गति से बढ़ी क्योंकि यात्रा सेवाओं में महामारी के बाद की वृद्धि का प्रभाव पिछले वर्षों में पहले ही समाप्त हो चुका है, साथ ही कम शिपिंग दरों के कारण परिवहन सेवाओं में धीमी वृद्धि हुई।

I.6 वैश्विक इक्विटी बाजार सुदृढ़ बने रहे, जो एआई से संबंधित प्रौद्योगिकी स्टॉक द्वारा समर्थित थे। हालांकि, टैरिफ अनिश्चितता, बढ़े हुए मूल्यांकन, अन्य सॉफ्टवेयर सेवाओं पर संभावित प्रभाव-विस्तार और बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव के बारे में चिंताओं ने अशांति की स्थितियाँ उत्पन्न की। अप्रैल 2025 - फरवरी 2026 के दौरान अमेरिकी डॉलर का मूल्यह्रास हुआ, लेकिन पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रकोप के बाद यह सुरक्षित निवेश की मांग के रूप में मजबूत हुआ। राजकोषीय चिंताओं के बीच सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल अधिक रहा, जिसमें इस संघर्ष ने ऊर्ध्वमुखी दबाव को और बढ़ाया।

घरेलू अर्थव्यवस्था

I.7 कई विपरीत परिस्थितियों के बीच स्थिर वैश्विक विकास की पृष्ठभूमि में, 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 7.1 प्रतिशत थी। मांग पक्ष पर, निजी अंतिम उपभोग व्यय और निश्चित निवेश ने प्रमुख विकास चालकों के रूप में कार्य किया। हालांकि अमेरिकी टैरिफ लगने से शुरू में चिंताएं पैदा हुईं, लेकिन उनका समग्र प्रभाव नगण्य रहा और समग्र वृद्धि में निवल निर्यात के चलते 0.1 प्रतिशत-अंक का मामूली अंतर पड़ा। आपूर्ति पक्ष पर, सेवा क्षेत्र में तेजी और मजबूत विनिर्माण प्रदर्शन ने मंद कृषि गतिविधि को संतुलित करने में मदद की।

I.8 2025-26[6] के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में योजित सकल मूल्य (जीवीए) में वृद्धि कम हुई, जो *खरीफ* फसलों में मौसम संबंधी व्यवधानों को दर्शाती है, हालांकि अनुकूल रबी परिस्थितियों ने समर्थन प्रदान किया। खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन के शुभारंभ के साथ-साथ दालों की आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू उपलब्धता में सुधार लाने पर केंद्रित नीतिगत प्रयास किए गए।

[4] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डबल्यूईओ), अप्रैल 2026, आईएमएफ़।
[5] ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स अपडेट, मार्च 2026, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)।
[6] 2025-26 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वास्तविक जीवीए में वृद्धि घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 4.2 प्रतिशत थी।

I.9 औद्योगिक क्षेत्र ने 2025-26 में मजबूत वृद्धि[7] दर्ज की, जो मजबूत विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित है। इस वृद्धि को स्थिर औद्योगिक ऋण वृद्धि और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन जैसी व्यापक क्षेत्रीय नीतियों द्वारा सुगम बनाया गया। विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ, जिसमें बुनियादी धातुओं, मोटर वाहनों और अन्य परिवहन उपकरणों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

I.10 भारत स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में विश्व स्तर[8] पर तीसरे स्थान पर है, जिसके पास 250 गीगावाट (जीडब्ल्यू) से अधिक की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता[9] है। स्वच्छ गतिशीलता क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री 2025-26 में 25 लाख इकाइयों से अधिक हो गई, जो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना जैसी पहलों से प्रेरित है। इसके साथ ही, ऑटोमोटिव क्षेत्र उत्तरोत्तर कम उत्सर्जन वाले विकल्पों को अपना रहा है, जिसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी), हाइब्रिड वाहन और ई-20 पेट्रोल शामिल हैं, जो टिकाऊ परिवहन के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

I.11 सेवा क्षेत्र कुल आपूर्ति का प्राथमिक चालक बना रहा, जो वास्तविक जीवीए वृद्धि में लगभग 69 प्रतिशत का योगदान देता है।[10] इस क्षेत्र के भीतर, 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवा, भंडारण' के साथ-साथ 'वित्तीय, रियल एस्टेट, आईटी और पेशेवर सेवा' जैसे खंडों में मजबूत विस्तार, उच्च-मूल्य वर्धित गतिविधियों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान श्रम बाजार की स्थिति स्थिर रही। कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट जारी रही, जबकि अन्य सेवाओं, विनिर्माण और व्यापार क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

I.12 केंद्र सरकार ने 2025-26 तक सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को जीडीपी से 4.5 प्रतिशत नीचे लाने के अपने राजकोषीय समेकन लक्ष्य को हासिल कर लिया। जीएफडी 2025-26 (आरई) में जीडीपी[11] का 4.4 प्रतिशत था, जो राजस्व व्यय में नियंत्रण और मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करों और गैर-कर राजस्व से उच्च राजस्व प्राप्तियों से प्रेरित था। कर राजस्व वृद्धि में मंदी और केंद्र से अनुदान में गिरावट के कारण अप्रैल 2025-फरवरी 2026 के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियां कम[12] हो गईं। कमी के बावजूद, राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। सोलहवें वित्त आयोग (2026-2031) ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान में ₹7,91,493 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव किया है। इसमें शहरीकरण की उभरती चुनौतियों का समाधान करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान में 194.3 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि शामिल है।[13]

I.13 हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 4.6 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 2.1 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप

7 एसएई के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में 2025-26 में 9.5 प्रतिशत की वास्तविक जीवीए वृद्धि दर्ज की गई (एक साल पहले यह 8.7 प्रतिशत थी)। विनिर्माण क्षेत्र में वास्तविक जीवीए वृद्धि 11.5 प्रतिशत रही (एक साल पहले यह 9.3 प्रतिशत थी)।

8 रिन्यूएबल केपेसिटी स्टेटिस्टिक्स 2026, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, मार्च 2026।

9 31 मार्च 2026 तक देश में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 283.5 गीगावॉट क्षमता स्थापित की गई। इसमें 274.7 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (150.3 गीगावॉट सौर ऊर्जा, 56.1 गीगावॉट पवन ऊर्जा, 11.7 गीगावॉट जैव ऊर्जा, 5.2 गीगावॉट छोटे जलविद्युत, 51.4 गीगावॉट बड़े जलविद्युत) और 8.8 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है [प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), 8 अप्रैल 2026]।

10 एसएई के अनुसार, सेवा क्षेत्र में वास्तविक जीवीए वृद्धि 2025-26 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो एक वर्ष पहले 7.8 प्रतिशत थी।

11 इस अध्याय में, केंद्र सरकार की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतकों की गणना जीडीपी श्रृंखला (2011-12 आधार वर्ष) का उपयोग करके की गई है। नई जीडीपी श्रृंखला (2022-23 आधार वर्ष) 2026-27 और 2022-23 से पहले के वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं है।

12 अनंतिम खातों से संबंधित डेटा 22 राज्यों से संबंधित हैं।

13 भारत में शहरीकरण, अर्थात् शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत, 2031 तक 40.7 प्रतिशत होने का अनुमान है (XVI वित्त आयोग की रिपोर्ट और यूएन वर्ल्ड अर्बनाइज़ेशन प्रोस्पेक्ट्स 2018)।

से खाद्य पदार्थों में नगण्य मूल्य दबाव और अनुकूल आधार प्रभाव से प्रेरित है। ईंधन में मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 और मार्च 2026 में प्रति लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में क्रमशः ₹50 और ₹60 वृद्धि से प्रेरित थी। खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति कीमती धातुओं (सोना और चांदी) की कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण स्थिर रही, जबकि सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने, वैश्विक स्तर पर पण्य की कीमतों में नरमी और इनपुट लागत के कम दबाव के कारण खाद्य, ईंधन और कीमती धातुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति सौम्य रही।

I.14 2025-26 के दौरान, विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता के चलते नीतिगत उपायों के लिए खुली गुंजाइश के साथ, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने जून 2025 से तटस्थ रुख बनाए रखते हुए नीतिगत रेपो दर में 100 आधार अंकों (बीपीएस) तक की कमी की। चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बनी रही, साथ ही चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण एक वर्ष पहले के ₹1,605 करोड़ से तीव्र गति से बढ़कर ₹1.86 लाख करोड़ हो गया। रिज़र्व बैंक ने खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) खरीद, यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप, लंबी अवधि के परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालन, और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की चार किस्तों में कुल 100 आधार अंकों की कटौती के माध्यम से प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि लगाई, जो परिचालन में मुद्रा और विदेशी मुद्रा परिचालन से आई कमी की भरपाई से अधिक है। वर्ष के दौरान भारित औसत माँग दर (डब्ल्यूएसीआर) नीतिगत रेपो दर से औसतन 7 बीपीएस कम थी।

I.15 वर्तमान नरमी के दौर (फरवरी 2025 से) के दौरान, बैंकों की जमा और उधार दरों में नीतिगत रेपो दर परिवर्तन का संचरण मजबूत रहा, जो अनुकूल चलनिधि स्थितियों द्वारा समर्थित था। कुल बकाया अस्थिर दर के ऋणों में बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) से जुड़े ऋणों के अनुपात में वृद्धि हुई, इसके साथ ही निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से जुड़े ऋणों में समवर्ती गिरावट आई।

I.16 बढ़ी हुई अनिश्चितता और अस्थिर पूंजी प्रवाह की पृष्ठभूमि में, घरेलू वित्तीय बाजारों में भी 2025-26 के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) और कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में वर्ष के दौरान वृद्धि संबंधी पूर्वाग्रह देखा गया। कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम में सुधार हुआ, जो बेहतर कॉरपोरेट तुलन-पत्रों द्वारा समर्थित है। टैरिफ के चलते तनाव के बीच बॉण्ड प्रतिफल और जोखिम प्रीमियम पर ऊर्ध्वमुखी दबाव को मौद्रिक नीति में नरमी और रिज़र्व बैंक द्वारा ओएमओ खरीद के साथ-साथ सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन पर निरंतर जोर देने से सीमित किया गया। घरेलू इक्विटी में वर्ष की पहली छमाही में तेजी देखी गई, हालांकि दूसरी छमाही में इसमें गिरावट दर्ज की गई, जिसका कारण मध्य पूर्व में भू-राजनैतिक तनाव में वृद्धि थी और साथ ही एआई से संबंधित मूल्यांकन-चिंताओं ने निवेशकों का रुख पर प्रभाव डाला था।

I.17 व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं, भू-राजनैतिक तनाव और इक्विटी खंड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह के बीच वर्ष के दौरान भारतीय रुपये (आईएनआर) ने मूल्यह्रास पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया। स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देने के प्रयासों ने जोर पकड़ा, साथ ही आईएनआर मूल्यवर्ग के चालान और निपटान धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। परिचालनगत रूप से, तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने में प्रगति जारी रही, जिसमें आईएसओ 20022 मैसेजिंग फ्रेमवर्क में सीमा-पार भुगतान का माइग्रेशन भी शामिल है।

I.18 भारत का पण्य व्यापार[14] घाटा 2025-26 के दौरान बढ़कर 333.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष पहले 283.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया। मजबूत सेवा

[14] 2025-26 के दौरान भारत के व्यापारिक निर्यात में 0.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी, और इस अवधि के दौरान व्यापारिक आयात में 7.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

व्यापार अधिशेष और निजी अंतरण प्राप्तियों में स्थिर प्रवाह ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान भारत के चालू खाते के घाटे को जीडीपी के 1.0 प्रतिशत के स्थायी स्तर के भीतर रखने में मदद की।

I.19 2025-26 के दौरान पूंजी प्रवाह में महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई। जहाँ निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में वृद्धि हुई, वहीं निवल विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) और निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जैसे पूंजी प्रवाह के अन्य प्रमुख रूपों में वर्ष के दौरान गिरावट[15] आई। बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं के संदर्भ में, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान निवल पूंजी प्रवाह सीएडी के वित्तपोषण से कम हो गया। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (बीओपी के आधार पर) में 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ (मार्च 2026 के अंत तक 691.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) लगभग 11 महीनों के आयात कवर और 90.3 प्रतिशत के बाह्य ऋण कवर सहित आरक्षित निधि पर्याप्तता के मानक मैट्रिक्स के संदर्भ में पर्याप्त रहा, जिससे प्रतिकूल वैश्विक प्रभाव-विस्तार के समक्ष बफर प्रदान किया गया।

I.20 वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण 2025-26 में 15.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (एक वर्ष पहले 10.9 प्रतिशत) बढ़ा। गैर-बैंक स्रोतों से ऋण में 13.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) [एक वर्ष पहले 15.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जो ऋण मध्यस्थता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। बैंक ऋण वृद्धि में सभी क्षेत्रों में गति प्राप्त हुई, जिसने जमा वृद्धि को पछाड़ दिया और ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हुई। आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ एससीबी की लाभप्रदता मजबूत बनी रही। जहाँ सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात बहु-दशकीय रूप से कम हो गया, वहीं पूंजी से जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) विनियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहा। तनाव परीक्षण के परिणामों ने बैंकों की सुदृढ़ता की पुष्टि की, जो विनियामक न्यूनतम स्तर से ऊपर पूंजी बफर को बनाए रखते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में नुकसान का सामना करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता वर्ष के दौरान मजबूत रही। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की ऋण और जमा वृद्धि में भी तेजी आई, साथ ही पूंजी बफर मजबूत हुआ और लाभप्रदता में सुधार आया।

I.21 वर्ष[16] के दौरान किए गए विनियामक प्रयास दो व्यापक उद्देश्यों पर आधारित रहे: पहला, विनियमित संस्थाओं (आरई) में मौजूदा अनुदेशों का सामंजस्य और समेकन; और दूसरा, क्रेडिट मध्यस्थता मॉडल और साधनों को विकसित करने के लिए स्पष्ट विवेकपूर्ण और आचरण-संबंधित सुरक्षा देना। 11,000 से अधिक परिपत्रों/अनुदेशों को 244 मास्टर निदेशों (एमडी) में समेकित किया गया। इन मास्टर निदेशों में 11 प्रकार की आरई से संबंधित विनियामक अनुदेशों के लगभग 30 कार्य/क्षेत्र समाहित हैं।

I.22 पर्यवेक्षी मोर्चे पर, रिज़र्व बैंक ने सुदृढ़ और मजबूत वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। पर्यवेक्षी पहलों[17] में, ये भी शामिल हैं: (ए) साइबर-धोखाधड़ी और अवैध धन वाहक गतिविधियों के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों और विभिन्न हितधारकों के साथ घनिष्ठ सहभागिता; (बी) बैंकिंग क्षेत्र में साइबर-सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए साइबर रेंज पहल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना;

[15] वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निवल एफडीआई अंतर्वाह 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2024-25 के 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत में निवल एफपीआई में 2024-25 के 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्वाह की तुलना में 2025-26 के दौरान 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया, जिसका मुख्य कारण इक्विटी बहिर्वाह था।

[16,17] विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय VI और अनुलग्नक-I में उपलब्ध है।

(सी) एनबीएफसी खंड के अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) का क्षेत्रीय जोखिम मूल्यांकन करना; और (डी) उन्नत सहयोग ढांचे और क्षमता-निर्माण पहलों के माध्यम से सीमा-पार पर्यवेक्षण को मजबूत करना। रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षण को मजबूत करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए प्रयास में सभी मौजूदा पर्यवेक्षी अनुदेशों को समेकित करते हुए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए नौ कार्यात्मक क्षेत्रों में 64 मसौदा मास्टर निदेश जारी किए।

I.23 2025-26 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने कई नवीन पहलें शुरू कीं। केंद्र और राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की प्रोग्रामेबिलिटी क्षमता का लाभ उठाते हुए कई सीबीडीसी पायलट लॉन्च किए गए। गुजरात, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को प्रोग्रामेबल सीबीडीसी के माध्यम से खाद्य सब्सिडी जमा की गई, जिसे उचित मूल्य की दुकानों/चिन्हित व्यापारियों पर पात्र वस्तुओं के लिए भुनाया जा सकता है। आस्ति टोकनाइजेशन पर, रिज़र्व बैंक ने यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस (यूएमआई) विकसित किया, जो निपटान क्षमता बढ़ाने के लिए थोक सीबीडीसी का लाभ उठाते हुए वित्तीय आस्तियों के टोकनाइजेशन की सुविधा के लिए एक बहु-स्तरीय प्लेटफॉर्म है। जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के टोकनाइजेशन पर यूएमआई पर एक पायलट शुरू किया गया। सीमा-पार भुगतान पर, रिज़र्व बैंक ने मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) के साथ डिजिटल आस्ति सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सीमा-पार सीबीडीसी पायलट के संचालन के लिए एमएएस और सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई (सीबीयूएई) के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। रिज़र्व बैंक सीबीडीसी के माध्यम से सीमा-पार भुगतान बढ़ाने पर केंद्रित बहुपक्षीय बीआईएस-इनोवेशन हब के नेतृत्व वाली पहलों अर्थात रियाल्टो, और प्रोजेक्ट मंडला का चरण 2 में भी शामिल हुआ।

I.24 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए फ्रेमवर्क (एफआरईई-एआई) समिति की रिपोर्ट, वित्तीय क्षेत्र में एआई के उपयोग हेतु मार्गदर्शन करने के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य संबंधित जोखिमों से सुरक्षा करते हुए इसकी क्षमता का उपयोग करना है। रिज़र्व बैंक समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों का आकलन कर रहा है, जो वित्तीय क्षेत्र में आरई और अन्य संस्थाओं के लिए अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन तैयार करने में मदद करेगा। इसके अलावा, सरकार ने जून 2025 में 'भारत जेन' लॉन्च किया, जो भारत का पहला सरकारी वित्तपोषित सोवरेन मल्टीलिंग्वल और मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं, अभिशासन और सार्वजनिक सेवा अनुप्रयोगों के अनुरूप एआई सिस्टम विकसित करना है। फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ-साथ दूरदर्शी प्रतिबद्धताओं और रणनीतिक साझेदारी को अपनाने के साथ संपन्न हुआ, जो एआई पर वैश्विक सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

I.25 भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) में 2025-26 के दौरान 11 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो देश भर में डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने और इसकी गहनता को दर्शाता है। खुदरा खंड के भीतर, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की मात्रा में 30 प्रतिशत (2024-25 में 42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो 200 बिलियन लेनदेन को पार कर गया। सीमा-पार विप्रेषण और व्यापारी भुगतान को सक्षम करने के लिए यूपीआई को अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़कर यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न का और विस्तार करने के प्रयास जारी हैं। वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान और निपटान पर किए गए विनियामक उपाय ग्राहक केंद्रितता, भुगतान प्रणालियों की सुदृढ़ता को मजबूत करने, धोखाधड़ी से निपटने और अधिक दक्षता लाने पर केंद्रित थे। इन उपायों में, *आधार* सक्षम

भुगतान प्रणाली (एईपीएस) को सुदृढ़ करना, भुगतान एग्रीगेटरों पर संबंधित निदेशों का समेकन, डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण तंत्र और चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान का कार्यान्वयन भी शामिल है।

I.26 रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक), जो देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापता है, मार्च 2024 के 64.2 से बढ़कर मार्च 2025[18] में 67.0 हो गया, जिसमें सभी तीन उप-सूचकांकों, अर्थात् पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में सुधार देखा गया। केवाईसी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 'केवाईसी - सुरक्षित बैंकिंग के लिए आपका पहला कदम' विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) 2026 मनाया गया। वित्तीय समावेशन पारितंत्र को और गहन बनाने एवं मजबूत करने के लिए दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई): 2025-30 जारी की गई।

I.27 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए और ग्रामीण सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल की पहुँच का विस्तार किया। लोकपाल ढांचे को और मजबूत करने और विनियमित संस्थाओं के स्तर पर शिकायतों के समाधान में दक्षता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 और 'विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल' पर मास्टर निदेश जारी किए गए। इसके अलावा पुनः-केवाईसी के लिए बाकी सभी खातों को शामिल करते हुए एक अभियान शुरू किया गया और शिकायत निवारण और अदावी जमाओं पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसका लाभ उठाया गया।

I.28 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के नागरिक चार्टर की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें विभिन्न सेवाओं के लिए समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है । संशोधित नागरिक चार्टर 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ, जो सेवा वितरण में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

3. 2026-27 के लिए संभावनाएं

वैश्विक अर्थव्यवस्था

I.29 2026 में भू-राजनैतिक जोखिम वैश्विक विकास में अंतर लाने वाले प्रमुख कारक के रूप में फिर से उभरा। फरवरी 2026 के अंत में पश्चिम एशिया में संघर्ष के फैलने का प्रतिकूल प्रभाव वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों में परिलक्षित होता है। आईएमएफ के आधारभूत परिदृश्य[19] में, 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है (जनवरी 2026 में 3.3 प्रतिशत के पहले के अनुमान की तुलना में), और वैश्विक वस्तु और सेवा व्यापार की मात्रा के 2026[20] में घटकर 2.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। संघर्ष की और तीव्रता, इसका लंबा होना या भौगोलिक प्रसार बढ़ना, यदि होता है तो, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के लिए प्रमुख अधोगामी जोखिम हैं।

I.30 निरंतर भू-राजनैतिक तनाव के साथ, मुद्रास्फीति को ऊर्ध्वगामी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ऊर्जा की बढ़ती कीमत और प्रमुख समुद्री -मार्गों में व्यवधान आपूर्ति-पक्ष के दबाव को तेज कर सकते हैं। आईएमएफ के आधारभूत परिदृश्य में, वैश्विक मुद्रास्फीति के जनवरी 2026 के 3.8 प्रतिशत पिछले अनुमान की तुलना में 2026 में 4.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय बाजार संकुचित समष्टि आर्थिक

18 'मार्च 2025 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक', रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति, 22 जुलाई 2025।

19 आईएमएफ का आधारभूत परिदृश्य मानता है कि युद्ध की अवधि, तीव्रता और गुंजाइश सीमित होगी और 2026 के मध्य तक व्यवधान फीके पड़ जाएंगे। कमोडिटी फ्यूचर्स की कीमतें 10 मार्च 2026 तक के अनुरूप ही रहने की संभावना है। (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2026, आईएमएफ)।

20 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डबल्यूईओ), अप्रैल 2026, आईएमएफ़।

स्थिति और जोखिम से बचने वाले व्यापक रुख के साथ उच्च अस्थिरता प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उच्च मूल्यन का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है, जिससे इक्विटी बाजारों में करेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है। बढ़ते संरक्षणवाद और डेट स्थिरता संबंधी चिंताओं के साथ, बढ़ते भू-राजनैतिक जोखिम राजकोषीय, मौद्रिक और बहुपक्षीय मोर्चों पर समन्वित नीतिगत कार्रवाइयों की मांग करते हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

I.31 मध्यम वैश्विक प्रगति की पृष्ठभूमि पर, 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, जो मजबूत समष्टि आर्थिक आधारभूत तत्वों द्वारा समर्थित है, हालांकि लंबे समय तक पश्चिम एशिया संघर्ष अधोगामी जोखिम पैदा कर सकता है। कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों के अच्छे तुलन-पत्र के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर जोर भारत के मजबूत प्रगति पथ के लिए अच्छा संकेत है। इसके अलावा, प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ विभिन्न व्यापार समझौते भारत की प्रगति को और गति प्रदान करेंगे।

I.32 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए परिदृश्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति और विस्तार पर निर्भर है। अल नीनो की स्थिति की संभावना कृषि उत्पादन के लिए अधोगामी जोखिम पैदा करती है। हालांकि, मानसून के मौसम के उत्तरार्ध में बारिश के लिए सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) की स्थिति उभरने की संभावना है, जो प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ मानसून भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, वहीं वर्षा परिवर्तनशीलता के साथ कृषि उत्पादन की संवेदनशीलता समय के साथ बढ़ती सिंचाई तीव्रता, बेहतर फसल प्रबंधन प्रथाओं और तकनीकी प्रगति के साथ कम हो गई है। हालांकि मौजूदा भू-राजनैतिक तनाव से प्रमुख वस्तुओं, विशेष रूप से उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है, फिर भी विविध स्रोतों और बफर प्रबंधन के माध्यम से उर्वरक और अन्य प्रमुख वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार के निरंतर प्रयासों से इन संभावित चिंताओं को कम करने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित पहल, विविधीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली फसल की खेती को लक्षित प्रोत्साहन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि की व्यावसायिक व्यवहार्यता बढ़ाने और *भारत*-विस्तार[21] के प्रस्तावित लॉन्च के साथ प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में अधिक प्रोत्साहन देने से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मजबूत और सतत प्रगति को समर्थन प्राप्त होगा।

I.33 भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों - इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, रेयर अर्थ, केमिकल, टेक्सटाइल और पूंजीगत माल - को केंद्रित नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिन्हित किया गया है। इसे पूरा करते हुए, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पीएलआई और पीएम ई-ड्राइव जैसे उपायों से ग्रीन टेक विनिर्माण को उत्प्रेरित करने और महत्वपूर्ण आयात निर्भरता को कम करने की उम्मीद है। इसके साथ ही फ्रेट कॉरिडोर, जलमार्ग, तटीय शिपिंग और सबसे दूरस्थ क्षेत्र तक कनेक्टिविटी में निवेश क्षेत्रीय एकीकरण को गहन बनाएगा और औद्योगिक विस्तार को समर्थन देगा। श्रम बाजार की स्थितियों में और सुधार होने की उम्मीद है, जो चार श्रम संहिताओं के पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन, घरेलू मांग और उत्पादकता को मजबूत करने से समर्थित है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, और इस धारणा पर कि पश्चिम एशिया संघर्ष का प्रतिकूल प्रभाव निकट अवधि में सीमित रहेगा, 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.9 प्रतिशत रहने

[21] *भारत*-विस्तार (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) कृषि स्तर पर बेहतर निर्णय लेने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाने हेतु एआई-आधारित सलाहकार प्रणालियों के साथ डिजिटल कृषि अवसंरचना को एकीकृत करने के लिए एक बहुभाषी उपकरण है।

का अनुमान[22] है, जिसके चलते रुख अधोगामी जोखिम की ओर बना हुआ है।

I.34 जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध विश्व स्तर पर समन्वित कार्रवाई के बारे में अनिश्चितता के बावजूद, भारत इस संबंध में अपने द्वारा किए जा रहे न्यूनीकरण और अनुकूलन उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) द्वारा निर्देशित है, जिसे 2031-35 की अवधि के लिए अद्यतन किया गया है। अद्यतित मात्रात्मक लक्ष्यों में गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 60 प्रतिशत प्राप्त करना, जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 47 प्रतिशत (2005 के स्तर से) तक कम करना और 2035 तक (2005 के स्तर से) 3.5-4.0 बिलियन टन CO_2 के बराबर कार्बन सिंक बनाना शामिल है।

I.35 विकास-प्रेरित पूंजीगत खर्च[23] पर केंद्र सरकार का रुझान जारी रहने की उम्मीद है। प्राप्तियों के मामले में, 2026-27 में प्रत्यक्ष करों का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतिशत है, जो एक दशक से अधिक समय में सबसे अधिक है। जीएफडी का 2026-27 में जीडीपी के 4.3 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जो हाल के वर्षों में केंद्र के राजकोषीय समेकन के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करने के लिए एक आर्थिक स्थिरीकरण कोष (ईएसएफ) की स्थापना की है। राज्यों के लिए राजकोषीय परिदृश्य 2026-27 के लिए सकारात्मक बना हुआ है और उनके समेकित जीएफडी का बजट सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)[24] का 3.0 प्रतिशत है। 2026-27 (बजट अनुमान) में राज्यों के सकल अंतरण में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जिसका मुख्य कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अंतरण और पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता है।

I.36 2026-27 में संभावित अल नीनो स्थितियों और सामान्य से अधिक गर्मी के तापमान के बावजूद पर्याप्त खाद्यान्न भंडार, पर्याप्त जलाशय स्तर और स्थिर कृषि संभावनाओं के कारण मुद्रास्फीति के लक्ष्य के अनुरूप रहने की संभावना है। हालांकि, कई अन्य कारकों जैसे भू-राजनैतिक तनाव के बीच वैश्विक ईंधन और पण्य-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, इनपुट और मजदूरी लागत में संभावित प्रभाव-अंतरण और विनिमय दर में अस्थिरता से मुद्रास्फीति के लिए उभरते ऊर्ध्वगामी जोखिम बढ़ सकते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के 4.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान[25] है, जिसमें रुख ऊर्ध्वगामी जोखिम की ओर है।

I.37 बढ़े हुए भू-राजनैतिक जोखिमों के बीच विकास-मुद्रास्फीति परिदृश्य संवेदनशील बना हुआ है, एमपीसी ने अप्रैल 2026 की अपनी बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, और तय किया कि सतर्क रहते हुए आने वाली सूचनाओं की सूक्ष्मता से निगरानी करेगा और जोखिमों के संतुलन का आकलन करेगा। एमपीसी ने तटस्थ रुख जारी रखने का भी फैसला किया, आने वाली सूचनाओं पर विवेकपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया देने के लचीलेपन को बरकरार रखा। इसके अलावा, अपनी दूसरी समीक्षा में, केंद्र सरकार ने रिज़र्व बैंक से विचार-विमर्श कर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए +/- 2 प्रतिशत के सहनशीलता-स्तर के साथ 4 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखा।

[22] मौद्रिक नीति वक्तव्य, अप्रैल 2026, भारतीय रिज़र्व बैंक।
[23] 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय, अर्थात् पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय और अनुदान सहायता, के जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जो 2025-26 (संशोधित अनुमान) में 3.9 प्रतिशत था।
[24] डेटा 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जिन्होंने 2026-27 के लिए मई 2026 के अंत तक अपना बजट प्रस्तुत किया है।
[25] मौद्रिक नीति वक्तव्य, अप्रैल 2026, भारतीय रिज़र्व बैंक।

I.38 यदि वैश्विक मौद्रिक सहजता चक्र रुक जाता है या मध्य पूर्व में नाजुक स्थितियों के बीच लगातार तेल की उच्च कीमतों के आघातों के प्रतिउत्तर में उलट जाता है तो इस स्थिति में घरेलू बॉण्ड प्रतिफल में ऊर्ध्वगामी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के साथ-साथ ओएमओ सहित रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि बढ़ाने के उपायों से प्रतिफल पर ऊर्ध्वगामी दबाव को नियंत्रित करने की उम्मीद है। इक्विटी बाजार की गतिशीलता को भू-राजनैतिक विकास, वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिरता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह के विकास से संतुलित किया जाएगा; अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के साथ-साथ जोखिम रुख में गिरावट से पूंजी बहिर्वाह हो सकता है। साथ ही, स्थानीय मुद्रा निपटान ढांचे का विस्तार करने के लिए चल रहे प्रयासों से भारतीय रुपये आधारित सीमा-पार लेनदेन को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

I.39 जहाँ वर्तमान में जारी भू-राजनैतिक संघर्ष और नीतिगत अनिश्चितता भारत के व्यापारिक निर्यात के लिए अधोगामी जोखिम पैदा करते हैं, वहीं कई व्यापार भागीदारों के साथ व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन और रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी और महत्वपूर्ण आयात निर्भरता कम होगी। इस दिशा में केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत प्रमुख पहलों में बायोफार्मा *शक्ति*[26], इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना का विस्तार, रेयर अर्थ कॉरिडोर का विकास, केमिकल पार्क की स्थापना और पूंजीगत वस्तुओं और कंटेनर निर्माण के लिए लक्षित समर्थन शामिल हैं। इसके अलावा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की स्थापना से डिजिटल सेवाओं के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करते हुए भौतिक/डिजिटल अवसंरचना निवेश को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में काम करने की उम्मीद है।

I.40 भारत के सेवा व्यापार संतुलन, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं और गैर-खाड़ी देशों से आवक विप्रेषण के लिए सुदृढ़ परिदृश्य से वर्ष 2026-27 के दौरान चालू खाता शेष में सहायता मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में डेटा केंद्रों के विकास हेतु विदेशी कंपनियों के लिए कर अवकाश[27] और सुरक्षित आश्रय[28] से संबंधित घोषणाएं, और भारत एआई शिखर सम्मेलन 2026 में 2047 तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अवसंरचनात्मक निवेश की प्रतिबद्धता, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए अच्छा संकेत है। इसके अतिरिक्त, उपग्रह विनिर्माण और उससे संबंधित घटकों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों को उदार बनाने और प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रह संचालन में वर्धित सीमा जैसे उपायों से इस क्षेत्र में वैश्विक पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने की उम्मीद है। एफपीआई के मामले में, प्रवाह वैश्विक जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर होगा। हालांकि, जारी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार करारों को अंतिम रूप देने से भारत के व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे 2026-27 के दौरान पूंजी अंतर्वाह होगा।

I.41 एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एआई पर वैश्विक सहयोग में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ। 92 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थित घोषणा-पत्र, आर्थिक विकास के लिए एआई का लाभ उठाने पर एक व्यापक-आधारित वैश्विक सहमति को दर्शाती है। वैश्विक स्तर पर, भारत

26 बायोफार्मा *शक्ति* (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए रणनीति) योजना, पांच वर्षों में ₹10,000 करोड़ का परिव्यय, जिसका उद्देश्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के उत्पादन के लिए भारत के पारितंत्र को मजबूत करना है।

27 भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी के लिए 2047 तक कर अवकाश की घोषणा की गई है।

28 यदि विदेशी कंपनी संबंधित इकाई है तो लागत पर न्यूनतम 15 प्रतिशत के सुरक्षित आश्रय का प्रस्ताव किया गया है, जबकि पूर्व में स्वतंत्र संव्यवहार के सिद्धांत के आधार पर ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रथा थी, जिसमें विवाद होने की संभावना थी।

को एआई प्रतिस्पर्धात्मकता और पारितंत्र जीवंतता के लिए रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।[29] मार्च 2024 में, सरकार ने 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इंडियाएआई मिशन शुरू किया। सामान्य गणना सुविधा के लिए 38,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) ऑनबोर्ड किए गए। सरकार की पहल से प्रेरित होकर निजी क्षेत्र भी एआई में तेजी से निवेश कर रहा है। एआई में भारत का संचयी निजी निवेश 2013 से 2024 के दौरान लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।[30] एफडीआई मार्केट्स के अनुसार, भारत 2024-25 में एआई से संबंधित उप-क्षेत्रों जैसे डेटा प्रोसेसिंग, और सेमीकंडक्टर व संबद्ध घटकों में वैश्विक ग्रीनफील्ड घोषणाओं में पांचवें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, भारत इनोवेट्स 2026 के लिए मई 2026 में पेरिस में आयोजित प्री-इवेंट रोड शो, भारत और विदेशों के व्यवसायों और नवाचार समूहों को एक साथ लाया, जिसका उद्देश्य भारतीय स्टार्ट-अप को वैश्विक निवेशकों, कंपनियों और अनुसंधान समूहों से जोड़ना है।

I.42 भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सुदृढ़ रहने की उम्मीद है, जो विवेकपूर्ण विनियामक सुधारों, स्थिर ऋण वृद्धि और पर्याप्त पूंजी बफर द्वारा समर्थित है। हालांकि, लंबे समय से चल रहे भू-राजनैतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान कॉरपोरेट आय और ऋण पोर्टफोलियो के प्रदर्शन के लिए निकट अवधि के जोखिम पैदा कर सकते हैं। वर्धित सॉवरेन प्रतिफल भी वित्तीय संस्थानों के निवेश पोर्टफोलियो पर दबाव डाल सकता है। फिर भी, संतुलन पर, मजबूत आधार और अच्छे तुलन-पत्र द्वारा समर्थित, घरेलू वित्तीय प्रणाली के पास प्रतिकूल आघातों का सामना करने के लिए पर्याप्त बफर उपलब्ध हैं।

I.43 विनियामकीय क्षेत्र[31] में, रिज़र्व बैंक का एजेंडा दो प्राथमिकताओं पर आधारित होगा: ग्राहक संरक्षण और ऋण बाजार में सुधार। ग्राहक सुरक्षा पर, केवाईसी ढांचे को मजबूत करने, एनआरआई ग्राहकों को वीडियो-आधारित पहचान का विस्तार करने और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण निदेशों की समीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऋण पक्ष पर, ब्याज दरों, ऋण जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम वितरण के लिए बाजार तंत्र पर निदेशों की समीक्षा के साथ-साथ साझा ऋण व्यवस्था के लिए एक नई रूपरेखा प्रस्तावित है। इसके अलावा, बैंकों के बोर्डों को उनके समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए और कार्यनीति और जोखिम अभिशासन के मामलों पर अधिक केन्द्रित और गुणात्मक भागीदारी के लिए, रिज़र्व बैंक विभिन्न मामलों को बोर्डों के समक्ष रखने के लिए अपने अनुदेशों से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाएगा।

I.44 2026-27 के दौरान रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी एजेंडा[32], उभरते जोखिमों की शीघ्र पहचान, मूल-कारण विश्लेषण को मजबूत करने और विनियमित संस्थाओं में पर्यवेक्षी प्रथाओं में स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इसमें एससीबी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की समीक्षा करना, माइक्रो-डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डेटा-संचालित पर्यवेक्षण को मजबूत करना और टियर 3 और टियर 4 यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) को विकसित करना शामिल होगा। रिज़र्व बैंक चुनिंदा एनबीएफसी और यूसीबी के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण ढांचे के कार्यान्वयन की भी जांच करेगा।

I.45 रिज़र्व बैंक ने डीबीटी योजनाओं और घरेलू खुदरा क्षेत्र के तहत नए उपयोग के मामलों को शामिल करने के लिए सीबीडीसी पायलट का विस्तार करने की योजना बनाई है, और इसके साथ वित्तीय आस्तियों के टोकनाइजेशन और प्रतिभागी कवरेज को व्यापक बनाने पर अतिरिक्त पायलट का पता लगाया जा रहा है। सीमा-पार भुगतान पर, रिज़र्व

[29] स्टेनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेनसी 2025 रिपोर्ट; पीआईबी, फरवरी 2026

[30] गूगल ने लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ विशाखापत्तनम में एक एआई हब की स्थापना की घोषणा की है और टाटा समूह ने महाराष्ट्र में एआई इनोवेशन सिटी के लिए 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है (पीआईबी, फरवरी 2026)।

[31,32] ब्यौरा इस रिपोर्ट के अध्याय VI में उपलब्ध है।

बैंक चुनिंदा उपयोग के मामलों के साथ द्विपक्षीय सीबीडीसी पायलट को संचालित करने और बहुपक्षीय परियोजनाओं में सहभागिता को गहन करने का उद्देश्य रखता है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) को अधिक डेटा सेवा-प्रदाताओं और उधारदाताओं की ऑनबोर्डिंग के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, और MuleHunter.ai™[33] को म्यूल रजिस्ट्री जैसी नई सुविधाओं के साथ अधिक बैंकों में विस्तारित किया जाएगा।

I.46 भारत में डिजिटल भुगतान की उल्लेखनीय वृद्धि की नींव पर और 'शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर' विषय पर आधारित, रिज़र्व बैंक का भुगतान विज़न 2028 दस्तावेज़, उपयोगकर्ता सशक्तिकरण, धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों, सीमा-पार भुगतान ढांचे की दक्षता और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने आदि पर केंद्रित है। अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से, विज़न दस्तावेज़ दिसंबर 2028 तक एक रोडमैप के रूप में काम करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की भुगतान प्रणालियाँ सुरक्षित, सुदृढ़, समावेशी और अभिनव बनी रहें। तदनुसार, 2026-27 के लिए, रिज़र्व बैंक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) के पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन और सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों के लिए 'स्विच-ऑन' और 'स्विच-ऑफ' सुविधा की शुरुआत करने का पता लगा रहा है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक धोखाधड़ी युक्त इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की अन्य श्रेणियों को शामिल करने हेतु ग्राहकों की देयता को सीमित करने के लिए मौजूदा निर्देशों के दायरे को व्यापक बनाकर और छोटे मूल्य के धोखाधड़ी युक्त इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए एक मुआवज़ा तंत्र शुरू करके डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

I.47 राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई): 2025-30 के तहत परिकल्पित कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ एफआई-सूचकांक की गणना के लिए एक संशोधित ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक सभी जिलों में प्रत्येक पात्र खाताधारक को यूपीआई, कार्ड, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) या एईपीएस में से कम से कम एक डिजिटल भुगतान माध्यम के साथ सक्षम करके डिजिटल वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाने का लक्ष्य बना रहा है।

I.48 आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं के स्तर पर शिकायत तंत्र पर व्यापक निर्देश जारी करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा, शिकायतों के समाधान के लिए रिज़र्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए उसका उन्नयन किया जा रहा है।

4. निष्कर्ष

I.49 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2025-26 में मजबूत निजी खपत, निरंतर निवेश और मजबूत समष्टि आर्थिक आधार के सहयोग से कई बाहरी प्रतिकूलताओं के बीच सुदृढ़ता प्रदर्शित की। आगे बढ़ते हुए, भारत का विकास परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, हालांकि पश्चिम एशिया संघर्ष और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, वित्तीय बाजार की अस्थिरता, वैश्विक व्यापार नीतियों में अनिश्चितता और मौसम से संबंधित व्यवधानों से जुड़े जोखिम अल्पावधि में विकास और मुद्रास्फीति के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का कारण बन सकते हैं। हालांकि, अच्छे कॉरपोरेट और बैंक तुलन-पत्र, पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर और प्रमुख भागीदारों के साथ व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन से निवेश और विकास की गति को बनाए रखने की उम्मीद है। फिर भी, अत्यधिक अनिश्चित वैश्विक परिवेश में, सतत आधार पर उपयुक्त नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए उभरते घटनाक्रमों का निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है।

[33] अवैध धन वाहक खातों की निकट-वास्तविक समय की पहचान करने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित एक पर्यवेक्षित एमएल उपकरण।